लिये जनवरी, 1974 में एक अन्तर-मंत्रालय समिति नियुक्त की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्तर मंत्रालय समिति ने मार्च, 1974 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उसने पहली अप्रैल, 1974 से कोयले के मूल्यों को बढ़ाने की सिफारिश की थी ;

(ग) क्या आर्थिक नीतियों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रस्ताव को पिछली तारीख से अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 से लागू करने के लिये 25 मई को अपनी स्वीकृति दी थी ;

(घ) यदि हां, तो कोयला कंपनियों को इस सम्भावित मूल्यवृद्धि का पूर्व संकेत क्यों नहीं दिया गया । जिसके कारण उनके द्वारा पहले ही बेच दिये गये कोयले पर बढ़ा हुआ मूल्य नहीं लिया जा सका । ;

(ङ) इस कारण कुल कितनी हानि हुई ; और

(च) क्या इस हानि के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नाथी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) अन्तर-मंत्रालीय समिति की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के कागजात बन गई जो गोपनीय होते हैं। मंत्रिमंडल के कार्यवृत्त भी गोपनीय होते है। चूंकि सरकार के अन्तिम निर्णय का पूर्व अनुमान लगाना संभव नहीं था अत: कोयला कंपनियों को इस संबंध में कोई भी पूर्व सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता ।

Preference to Indigenous Technique in Power Generation

1141. SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government give preference to indigenous industries against foreign technical know-how and foreign companies in the matter of power generation.

(b) if so, whether this policy is followed while issuing global tender notices; and

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, how Government propose to avoid complication later when in case of global tenders preference is shown to indigenous industries against foreign companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir. Primary reliance continues to be on indigenous sources for procurement of power equipment.

(b) and (c) Under the Present import policy of the Government, State Electricity Boards are permitted to float global tenders for power equipment irrespective of whether some of the equipment are manufactured indigenously or not. The selection of suppliers on the basis of such global tenders, foreign or Indian, is subject to scrutiny by a Committee set up in the Department of Heavy Industry, which takes into consideration all the relevant factors. Further import of generating equipment is resorted to selectively in cases where the poject is tied up for assistance from World Bank or bilateral or multilateral assistance.

Internal Audit of Assam Petro-Chemicals Limited

1142. SHRI ROBIN KAKATI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether various irregularities of a serious nature and misuse of fund have been pointed out in the Internal Audit report, submitted by Assam Petro-chemicals Limited Internal Audit Cell a few months ago;